[2023] 4 एस.सी.आर. 851

तमिलनाडु सरकार एवं अन्य

बनाम

आर. थामराइसेल्वम इत्यादि.इत्यादि.

(2022 की दीवानी अपील संख्या 1580-1608)

04 मई, 2023

[एम. आर. शाह एवं बी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्तिगण]

भूमि हथियाना : भूमि हथियाने के मामले – एक सरकारी आदेश द्वारा, तमिलनाडु राज्य ने भूमि हथियाने से संबंधित मामलों की जाँच के लिए तमिलनाडु में भूमि हथियाने के खिलाफ विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया, हालाँकि, इसमें भूमि हथियाने के मामलों को परिभाषित नहीं किया गया था – दूसरे सरकारी आदेश द्वारा भूमि हथियाने के मामलों को विशेष रूप से ऐसे मामलों से निपटने के लिए गठित विशेष न्यायालयों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था – उक्त सरकारी आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाएँ दायर की गईं – उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेशों को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि वे भूमि हथियाने में शामिल माने जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट मामलों को चुनने या चयन करने के लिए कोई मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करते हैं, और "भूमि हथियाना" शब्द/वाक्यांश की परिभाषा के अभाव में, एंटी-लैंड ग्रैबिंग सेल से जुड़े पुलिस कर्मियों को यह अबाधित विवेक प्राप्त होता है कि वे किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना चाहते हैं, और इस प्रकार, शक्ति के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल की संभावना है – अन्य सरकारी आदेश भी अभिखंडित कर दिया गया – अपील पर, अभिनिर्धारितः भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियमन और/या अधिनियम नहीं है – यह निर्धारित करने के लिए किसी भी दिशानिर्देश और/या परिभाषा के अभाव में कि किन मामलों को भूमि हथियाने के मामले कहा जा सकता है, यह पुलिस को असीमित, अनियंत्रित

और मनमानी शक्तियाँ देता है कि वे किसी भी भूमि मामले को भूमि हथियाने का मामला मान सकती है, जिसकी जाँच एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल द्वारा की जाएगी – इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उपयुक्त कानून लाने की स्वतंत्रता के साथ सरकारी आदेश को सही ढंग से अपास्त कर दिया – उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की दीवानी अपील संख्या 1580-1608।

उच्च न्यायालय, मद्रास के दिनांक 10/02/2015 के डब्ल्यू.पी.संख्या 26883, 27216/2011, 24925/2013, 27502/2011, 10198, 28060/2012, 28413/2014, डब्ल्यू.पी.एम.डी.संख्या 19726/2014, डब्ल्यू.पी. संख्या 25877, 26773/2011, 10775/2012, 20481/2014, 18872, 21126, 25876, 27215, 27503, 27504, 27505/2011, 8227, 8261, 10185, 25834, 26956, 26957/2012, 4476, 31673/2014, 26884/2011, 26885/2015 में दिए गए निर्णय और आदेश से।

के साथ

2022 की आपराधिक अपील संख्या 275

आर. षणमुगसुंदरम, महाधिवक्ता, वी. कृष्णमूर्ति, अतिरिक्त महाधिवक्ता, डॉ. राम शंकर, के. एलांगोवन, एल. शिवकुमार, शारू कुमार, सुवेथन, सुश्री सुजाथा बागधी, सुश्री शारूमति, यूसुफ, बी. बालाजी, डॉ. जोसेफ एरिस्टोटल एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री नूपुर शर्मा, संजीव कुमार महारा, एस. थनंजयन, सुश्री ऐना वर्मा, सुश्री जसवंती अनबुसेल्वम, सुश्री प्रोमिला, के.एस. महादेवन, रंगराजन, सुश्री स्वाति बंसल, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाला, टी. आर. बी. शिवकुमार, बी. श्रीधर, वेंकटेश्वरा राव अनुमोलु, एस. गौथमन, आर. नेदुमारन, के.वी. जगदीश्वरन, सुश्री एन.पी. हैबिला, सुश्री जी. इंदिरा, अनिश आर. शाह, एम.पी. श्रीविग्नेश, मिथुनकुमार एन., जोस अब्राहम, आदि उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या 18872/2011 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं में दिनांक 10.02.2015 को पारित सामान्य निर्णय और आदेश से असंतुष्ट और व्यथित होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और सरकारी आदेश (एम.एस.) संख्या 423, गृह (पुलिस XI) विभाग दिनांक 28.07.2011 (जिसे इसके बाद 'सरकारी आदेश संख्या 423 दिनांक 28.07.2011' कहा जाएगा) के साथ-साथ सरकारी आदेश (एम.एस.) संख्या 451, गृह (न्यायालय III) विभाग दिनांक 11.08.2011 (जिसे इसके बाद 'सरकारी आदेश संख्या 451 दिनांक 11.08.2011' कहा जाएगा) को अभिखंडित कर दिया है, तमिलनाडु राज्य ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

1.1 आपराधिक अपील संख्या 275/2022 मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आपराधिक ओ.पी. संख्या 23641/2019 में दिनांक 04.11.2020 को पारित आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायिक दंडाधिकारी, भूमि हथियाना, इरोड के न्यायालय से सी.सी. संख्या 2/2012 मामले को न्यायिक दंडाधिकारी-द्वितीय, इरोड के अभिलेख में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

2. सरकारी आदेश संख्या 423 दिनांक 28.07.2011 *के माध्यम से*, तमिलनाडु राज्य ने राज्य में भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल के गठन को मंजूरी दी, जिसमें राज्य पुलिस मुख्यालय, 7 कमिश्नरेट और 28 जिलों में एक-एक सेल शामिल था। उक्त सरकारी आदेश के परिणामस्वरूप, एक और सरकारी आदेश संख्या 451 दिनांक 11.08.2011 जारी किया गया और भूमि हथियाने के मामलों को विशेष न्यायालयों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया, जिनका गठन विशेष रूप से भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए किया गया था। उपरोक्त सरकारी आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का विषय थे।

2.1 आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश संख्या 423 दिनांक 28.07.2011 को यह मानते हुए अपास्त कर दिया कि यह भूमि हथियाने में लिप्त माने जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट मामलों को चुनने और चयन करने के लिए कोई मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करता है, और "भूमि हथियाना" शब्द/वाक्यांश की परिभाषा के अभाव में, एंटी-लैंड ग्रैबिंग सेल से जुड़े पुलिस कर्मियों को यह विवेक प्राप्त होता है कि वे किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना चाहते हैं और जाँच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके कारण, शक्ति के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सरकारी आदेश संख्या 423 दिनांक 28.07.2011 को अभिखंडित और अपास्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि राज्य सरकार ए.पी. लैंड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम, 1982 की तर्ज पर या रिट याचिकाओं के परिणाम से परे बेहतर कानून लाने के लिए स्वतंत्र है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश संख्या 451 दिनांक 11.08.2011 को भी अभिखंडित और अपास्त कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान दीवानी अपीलों का विषय है।

3. तमिलनाडु राज्य की ओर से श्री आर. षणमुगसुंदरम, विद्वान महाधिवक्ता उपस्थित हुए हैं।

3.1 तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए सरकारी आदेशों को अभिखंडित करने में त्रुटि की है कि "भूमि हथियाने" के अपराध से संबंधित परिभाषा के अभाव में, भूमि हथियाने से संबंधित मामलों की जाँच के लिए गठित विशेष सेल उन प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिए सक्षम नहीं हैं।

3.2 आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल की संभावना के आधार पर सरकारी आदेश संख्या 423 दिनांक 28.07.2011 को अभिखंडित और अपास्त करने में त्रुटि की है। यह कि

किसी प्रावधान के प्राधिकरण द्वारा दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल की संभावना किसी कानून को मनमाना या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानने का आधार नहीं हो सकती।

3.3 इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय यह सराहना करने में विफल रहा कि विशेष सेल का गठन तमिलनाडु राज्य में विशिष्ट समस्या से निपटने के लिए किया गया था, जहाँ बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि *गुंडों* ने अपनी बाहुबल का उपयोग करके जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया है।

3.4 यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय को यह सराहना करनी चाहिए थी कि "भूमि हथियाना" अभिव्यक्ति को किसी विशिष्ट परिभाषा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 420 और 506 से संबंधित है।

4. हमने तमिलनाडु राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता को विस्तार से सुना। हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश का अध्ययन किया है। हमने सरकारी आदेश संख्या 423 दिनांक 28.07.2011 का भी अध्ययन किया है, जो इस प्रकार है:

"गृह (पॉल-XI) विभाग

सरकारी आदेश (एम.एस.) संख्या 423 दिनांक: 28.07.2011

पुलिस महानिदेशक, चेन्नई-4, के पत्र संदर्भ में: संख्या: 176388/आर.ए.आई.(2)/2011, दिनांक: 13.07.2011

<u>आदेश:-</u>

दिनांक: 10.07.2011 की प्रेस विज्ञप्ति में, माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि राज्य में भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए तमिलनाडु में एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा।

2. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के आधार पर, पुलिस पुलिस महानिदेशक ने

27,71,11,658/- रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ, राज्य में भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए 410 पुलिस कर्मियों के साथ 39 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल के गठन हेतु सरकार को आवश्यक प्रस्ताव भेजे हैं।

3. सरकार ने गहन जाँच के बाद, पुलिस महानिदेशक के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया है और करूरु, तिरुवन्नामलाई और नागपट्टिनम जिलों को छोड़कर, राज्य पुलिस मुख्यालय, 7 कमिश्नरेट और 28 जिलों में से प्रत्येक में एक सेल के साथ, तमिलनाडु में 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल के गठन के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु अस्थायी आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन तीन जिलों के मामले में, जिला अपराध शाखा भूमि हथियाने की शिकायतों की जाँच संभालेगी। तमिलनाडु में 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल का स्टाफ पैटर्न इस आदेश के अनुलग्नक-I में इंगित किया गया है। सरकार 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल के गठन के लिए 20,02,08,842/- रुपये (बीस करोड़, दो लाख, आठ हजार, आठ सौ बयालीस रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करती है। इस आदेश के अनुलग्नक-II से IV में इंगित अनुसार, आवर्ती और अनावर्ती व्यय क्रमशः 12,51,01,380/- रुपये और 7,51,07,462/- रुपये हैं।

4. उपरोक्त कंडिका 3 में स्वीकृत व्यय को संबंधित निम्नलिखित खाता शीर्ष के तहत नामे किया जाएगा: "2055-00-पुलिस – संबंधित उप-शीर्षों के तहत"

5. व्यय "नई सेवा" का एक मद है। विधानमंडल की स्वीकृति नियत समय में प्राप्त की जाएगी। विधानमंडल की स्वीकृति लंबित रहने तक, व्यय को शुरू में आकस्मिकता निधि से अग्रिम द्वारा पूरा किया जाएगा, जिसके संबंध में आदेश वित्त (बीजी.आई) विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक, चेन्नई से अनुरोध किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में चालू वर्ष में आकस्मिकता निधि से आवश्यक राशि के अग्रिम के लिए सरकार के वित्त (बीजी.आई) विभाग में आवेदन करें। उन्हें योजना की कुल लागत, वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए आवश्यक लागत आदि को दर्शाते

हुए एक मसौदा व्याख्यात्मक नोट भी सरकार के वित्त (बीजी-आई) विभाग को भेजने का निर्देश दिया जाता है ताकि इसे पूरक अनुमानों में शामिल किया जा सके और नियत समय में विधानमंडल के संज्ञान में लाया जा सके।

6. यह आदेश वित्त विभाग की यू.ओ. संख्या 39471/सी.एम.पी.सी./2011-1, दिनांक 28.07.2011 और अतिरिक्त स्वीकृति खाता बही संख्या: 337 (तीन सौ सैंतीस) की सहमति से जारी किया जाता है।

(राज्यपाल के आदेश से)

रमेशराम मिश्रा

सरकार के प्रधान सचिव"

5. उपरोक्त सरकारी आदेश द्वारा, तमिलनाडु सरकार ने भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल का गठन/निर्माण किया है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि किस प्रकार के मामलों को भूमि हथियाने के मामले कहा जा सकता है, यह उक्त सरकारी आदेश में परिभाषित और/या उल्लेखित नहीं किया गया है। इसलिए, यह संबंधित पुलिस अधिकारियों के विवेक पर होगा कि वे भूमि से संबंधित किसी भी मामले को भूमि हथियाने का मामला मानें और/या विचार करें, जिसकी जाँच एंटी-लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल द्वारा की जाएगी, न कि सी.आर.पी.सी. के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि तमिलनाडु राज्य में ए.पी. लैंड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम, 1982 या कर्नाटक लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन अधिनियम, 2011 या अन्य राज्यों में समान भूमि हथियाने निषेध अधिनियमों जैसा कोई एंटी-लैंड ग्रैबिंग अधिनियम नहीं है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और असम राज्यों में लागू होने वाले अन्य भूमि हथियाने निषेध अधिनियमों में, "भूमि हथियाना" को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। यहाँ तक कि “भूमि हथियाने वाला” शब्द भी परिभाषित है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश लैंड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम, 1982 में, “भूमि हथियाने

वाला" और "भूमि हथियाना" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "भूमि हथियाने वाला" का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो भूमि हथियाने का कार्य करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने के लिए या उस पर अनधिकृत संरचनाओं के निर्माण के लिए किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता देता है, या जो आपराधिक धमकी द्वारा ऐसी भूमि के किसी भी कब्जाधारी से किराया, मुआवजा और अन्य शुल्क वसूलता है या वसूलने का प्रयास करता है, या जो ऊपर उल्लिखित किसी भी कार्य को दुष्प्रेरित करता है; और इसमें हित उत्तराधिकारी भी शामिल हैं।
>
> "भूमि हथियाना" का अर्थ है किसी भी भूमि (चाहे वह सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था या बंदोबस्ती, जिसमें वक्फ शामिल है, या किसी अन्य निजी व्यक्ति की हो) को बिना किसी कानूनी अधिकार के और ऐसी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने, या ऐसी भूमि के संबंध में अवैध किरायेदारी या पट्टे और लाइसेंस समझौते या किसी अन्य अवैध समझौते में प्रवेश करने या बनाने, या बिक्री या किराये के लिए उस पर अनधिकृत संरचनाओं का निर्माण करने, या निर्माण, या अनधिकृत संरचनाओं के उपयोग और कब्जे के लिए किराये या पट्टे और लाइसेंस के आधार पर ऐसी भूमि किसी व्यक्ति को देने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा हथियाने की प्रत्येक गतिविधि; और "हथियाना" शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा।

6. जहाँ तक तमिलनाडु राज्य का संबंध है, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियमन और/या अधिनियम नहीं है, जैसे कि आंध्र प्रदेश लैंड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम, 1982, और एंटी-लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल का गठन विशेष रूप से भूमि हथियाने के मामलों से निपटने के लिए सरकारी आदेश संख्या 423, दिनांक 28.07.2011 द्वारा किया गया है। यह निर्धारित करने के लिए किसी भी

दिशानिर्देश और/या परिभाषा के अभाव में कि किन मामलों को भूमि हथियाने के मामले कहा जा सकता है, यह पुलिस को असीमित, अनियंत्रित और मनमानी शक्तियाँ देता है कि वे किसी भी भूमि मामले को भूमि हथियाने का मामला मान सकती है, जिसकी जाँच एंटी-लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल द्वारा की जाएगी। यहाँ तक कि दो निजी व्यक्तियों के बीच का विवाद जो विशिष्ट राहत अधिनियम और/या संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत हो सकता है, उसे भी भूमि हथियाने का मामला माना जा सकता है, जैसा कि आपराधिक अपील संख्या 275/2022 में हुआ था, जिसमें विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक दीवानी वाद लंबित था जिसे गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था और उसके बाद उत्तरदाता ने भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए एक शिकायत/प्राथमिकी दर्ज की थी। इसलिए, इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा यह सही ढंग से माना और टिप्पणी की गई है कि "भूमि हथियाने के मामलों" की किसी विशिष्ट दिशानिर्देश और/या परिभाषा के अभाव में, ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी शक्तियों को मनमाने ढंग से प्रयोग किया गया कहा जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश संख्या 423 दिनांक 28.07.2011 को अपास्त करके सही किया, साथ ही राज्य सरकार को ए.पी. लैंड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम, 1982 की तर्ज पर या बेहतर कानून लाने की स्वतंत्रता दी, "भूमि हथियाने के मामले" कहे जाने वाले अपराधों को परिभाषित करने और/या दिशानिर्देश प्रदान करने के बाद। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/निर्णयों और आदेश/आदेशों में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. परिस्थितियों के तहत, राज्य द्वारा दायर दीवानी अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। हालाँकि, हम यह दोहराते हैं कि यदि राज्य सरकार भूमि हथियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जागरूक और/या इच्छुक है, तो राज्य सरकार के लिए "भूमि हथियाने वाले" और "भूमि हथियाना" की स्पष्ट परिभाषा के साथ एक उपयुक्त कानून लाना या "भूमि हथियाना", "भूमि हथियाने वाले" और "भूमि हथियाने के

मामलों" की स्पष्ट परिभाषा के साथ बेहतर कानून लाना स्वतंत्र होगा और वर्तमान आदेश ऐसे कानून और/या बेहतर कानून बनाने में बाधा नहीं बनेगा।

8. उपरोक्त के मद्देनज़र, आपराधिक अपील संख्या 275/2022 जो निजी व्यक्तियों से संबंधित थी, जिसके द्वारा पक्षों के बीच आपराधिक मामले को विशेष न्यायालय (भूमि हथियाना) से नियमित न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था, खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

निधि जैन अपीलें खारिज की गई।

(सहायता: राखी, एल.सी.आर.ए.)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।